



भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता

प्रलम्ब के लिये:

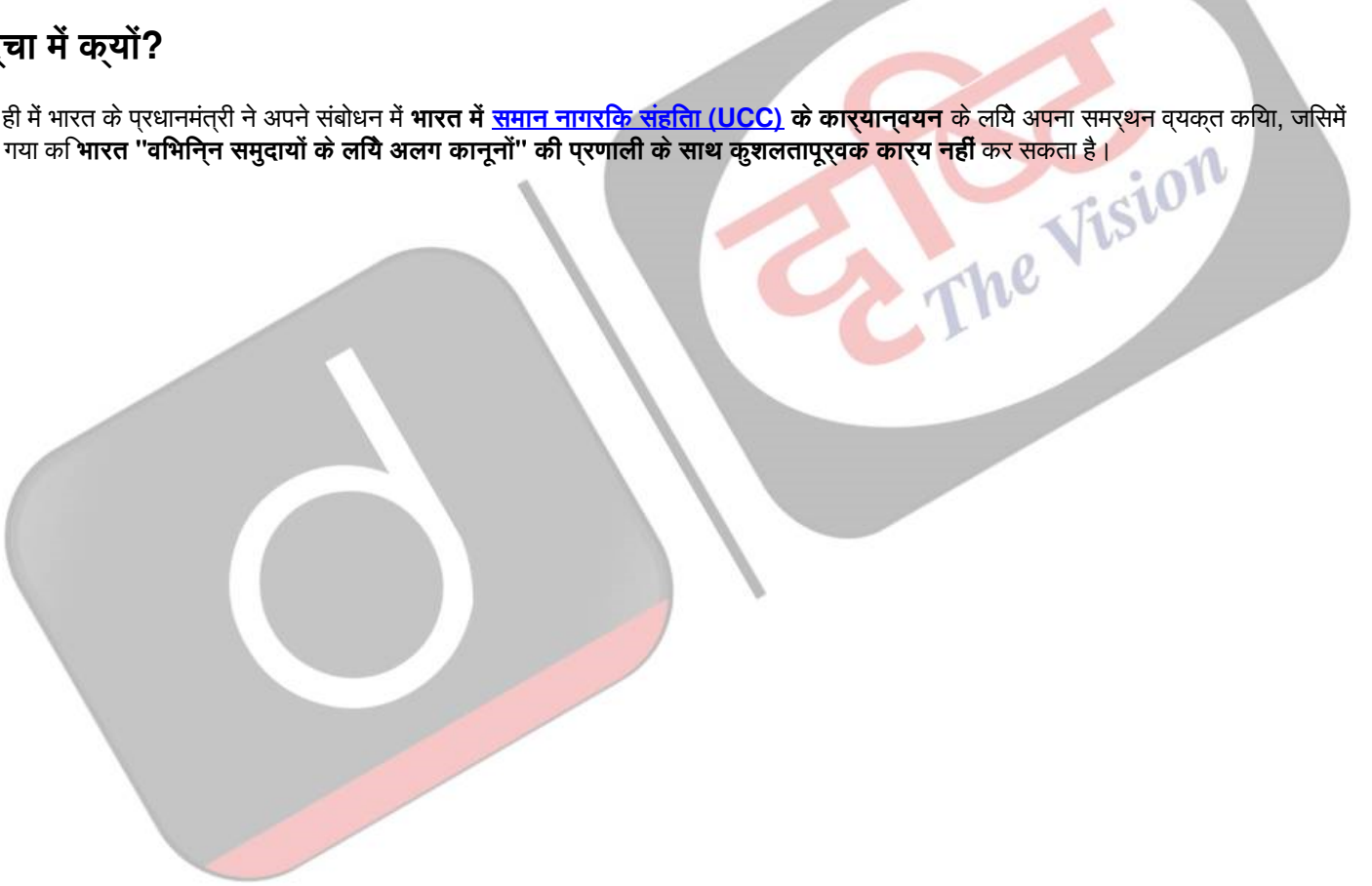
[समान नागरिक संहिता](#), [संविधान का अनुच्छेद 44](#), [सातवीं अनुसूची](#), [वर्ष 1954 का विशेष विवाह अधिनियम](#), [भारत का 22वाँ वधिआयोग](#)

मेन्स के लिये:

समान नागरिक संहिता के पक्ष और विपक्ष में तर्क, भारत में समान नागरिक संहिता के लिये प्रयास, समान नागरिक संहिता को लागू करने में चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत में [समान नागरिक संहिता \(UCC\)](#) के कार्यान्वयन के लिये अपना समर्थन व्यक्त किया, जिसमें कहा गया कि भारत "वभिन्न समुदायों के लिये अलग कानूनों" की प्रणाली के साथ कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है।





UNIFORM CIVIL CODE

All sections of the society irrespective of their religion shall be treated equally according to a National Civil Code - the Uniform Civil Code.

THEY COVER AREAS LIKE



Marriage



Divorce



Maintenance



Inheritance



Adoption



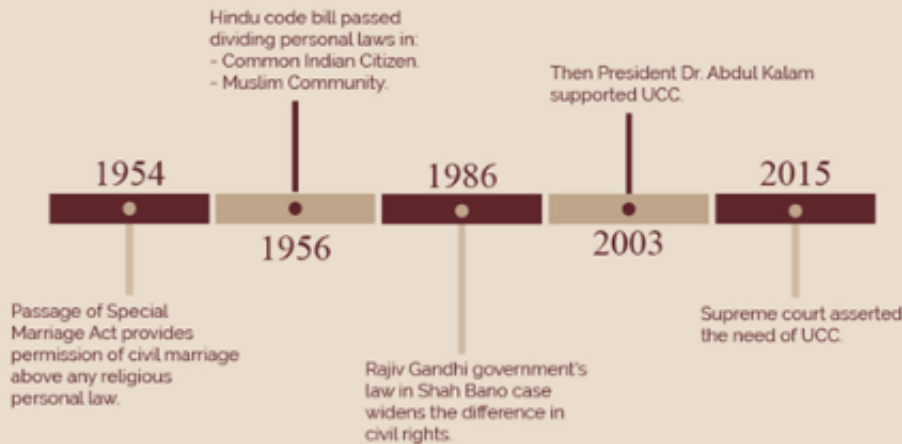
Succession of Property

It is based on the premise that there is necessarily no connection between religion and personal law in a civilized society.

"UCC refers to a common set of laws governing civil rights of every citizen."

Article 44 of Directive Principles sets duty of state for implementing UCC.

TIMELINE



The dialogue for UCC was started by the Law Commission in the year 2016

समान नागरिकी संहिता (UCC):

■ उत्पत्ति और इतिहास:

- औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार की वर्ष 1835 की रिपोर्ट में अपराध, साक्ष्य और अनुबंध सहित भारतीय कानून में एक समान संहिताकरण का आह्वान किया गया था।
 - हालाँकि, अक्टूबर 1840 की लेक्स लोकी रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिये।
- जैसे-जैसे ब्रिटिश शासन आगे बढ़ा हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिये वर्ष 1941 में बी.एन. राऊ समिति का गठन किया गया। इस गठन के परिणामस्वरूप वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू हुआ।

■ समान नागरिकी संहिता पर संविधान सभा के विचार:

- संविधान सभा में बहस के दौरान समान नागरिकी संहिता को शामिल करने पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई।
 - जहाँ सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में मतदान हुआ और 5:4 के अनुपात में बहुमत मिला जिसके परिणामस्वरूप मौलिक अधिकारों पर उप-समिति ने नरिणय लिया कि समान नागरिकी संहिता को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा।

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार करते समय कहा था कसिमान नागरिकि संहति वांछनीय है लेकनि इसे तब तक सवैच्छिकि रहना चाहिये जब तक किराष्टर इसे सवीकार करने के लिये सामाजिक रूप से तैयार न हो जाए।
- जिसके परिणामस्वरूप समान नागरिकि संहति को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) ([अनुच्छेद 44](#)) में रखा गया।

नोट: भारत में विवाह, तलाक, वरिसत जैसे परसनल लॉ के विषय समवर्ती सूची ([7वीं अनुसूची](#)) के अंतर्गत आते हैं।

समान नागरिकि संहति के पक्ष में तर्क:

- **विविधता में एकता का जशन मनाना:** यह व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों के आधार पर भेदभाव और वरिधाभासों को दूर करके तथा सभी नागरिकों के लिये एक समान पहचान स्थापित कर राष्ट्रीय एकता एवं [धर्मनिरपेक्षता](#) को बढ़ावा देगी।
 - यह विविधि समुदायों के बीच एकता और सद्भाव की भावना को भी बढ़ावा देगी।
 - उदाहरण स्वरूप UCC बना कसिनी कानूनी बाधा या सामाजिक दुष्प्रभाव के [अंतर-धार्मिक विवाह](#) और संबंधों को सक्षम बनाएगा।
- **महिलाओं को सशक्त बनाना:** यह विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों, जैसे- [बहुविवाह](#), असमान वरिसत आदि में महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण और दमनकारी प्रथाओं को समाप्त करके लैंगिक न्याय और समानता सुनिश्चित करेगा।
- **कानूनी दक्षता के लिये इसे सरल बनाना:** भारत की वर्तमान कानूनी प्रणाली जटिल और अतवियापी व्यक्तिगत कानूनों की अधिकता है, जिससे भ्रम और कानूनी विवाद पैदा होते हैं।
 - एक UCC विभिन्न कानूनों को एक ही कोड में समेकित और सुसंगत बनाकर कानूनी ढाँचे को सरल बनाएगा।
 - इससे स्पष्टता बढ़ेगी, कार्यान्वयन में आसानी होगी और [न्यायपालिका](#) पर बोझ कम होगा, जिससे अधिक कुशल कानूनी प्रणाली सुनिश्चित होगी।
- **सफलता की वैश्विक कहानियों से प्रेरणा लेना:** फ्रांस जैसे दुनिया भर के कई देशों ने समान नागरिकि संहति लागू की है।
 - UCC एक आधुनिक प्रगतशील राष्ट्र का संकेत है जिसका अर्थ है कि इसे जातगत और धार्मिक राजनीतिको रोका जा सकेगा।

UCC के विरोध में तर्क:

- **अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खतरा:** भारत की शक्ति इसके विविध समाज में नहि है और इन विविधताओं को समायोजित करने के लिये व्यक्तिगत कानून विकसित किये गए हैं।
 - आलोचकों का तर्क है कि एकल संहति लागू करने से अल्पसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वायत्तता कमजोर हो सकती है, जिससे अलगाव एवं हाशिये की स्थितिकी भावना पैदा हो सकती है।
- **न्यायिक बैकलॉग:** भारत पहले से ही न्यायिक मामलों के एक [महत्त्वपूर्ण बैकलॉग](#) का सामना कर रहा है तथा UCC को लागू करने से स्थिति और खराब हो सकती है।
 - व्यक्तिगत कानूनों को एक कोड में सुसंगत बनाने के लिये आवश्यक व्यापक महत्त्वपूर्ण कानूनी सुधारों हेतु समय और प्रयास की आवश्यकता होगी।
 - परिणामस्वरूप इस संक्रमणकालीन अवधि के दौरान UCC की संवेधानिकता को चुनौती देने वाले नए मामलों के उभरने के कारण कानूनी प्रणाली पर बोझ बढ़ सकता है।
- **गोवा में UCC को लेकर जटिलताएँ:** गोवा में UCC के कार्यान्वयन की वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने सराहना की है। हालाँकि ज़मीनी हकीकत राज्य के UCC के भीतर जटिलताओं और कानूनी बहुलताओं को उजागर करती है।
 - गोवा में UCC हद्दियों को एक विशिष्ट प्रकार के बहुविवाह की अनुमति देता है और मुसलमानों हेतु शरीयत अधिनियम का वसितार नहीं करता है (यह पुरतगाली और शास्त्री हद्दिकानून पर आधारित हैं)।
 - इसके अतिरिक्त कैथोलिक को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जैसे- विवाह पंजीकरण से छूट तथा कैथोलिक पादरियों की विवाह को विधित करने की शक्ति।
 - यह भारत में व्यक्तिगत कानूनों की जटिलता को उजागर करता है, यहाँ तक कि इस राज्य में भी जो UCC लागू करने के लिये जाना जाता है।

भारत में UCC की दशा में प्रयास:

- **सांविधिकि प्रावधान:**
 - [विशेष विवाह अधिनियम, 1954](#): इस अधिनियम के अंतर्गत कसिनी भी धर्म के भारतीय नागरिक को धार्मिक रीति-रिवाज़ से बाहर विवाह करने की अनुमति है।
- **UCC की आवश्यकता की सफिरशि करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय:**
 - शाहबानो केस, 1985
 - सरला मुद्गल केस, 1995
 - पाउलो कॉटनिहो बनाम मारथिया लुइज़ा वेल्लेंटीना परेरा (2019)
- **UCC से विधिआयोग तक का रुख:**
 - भारतीय विधिआयोग (2018): इसमें कहा गया है कि UCC, इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है, क्योंकि यह राष्ट्र की सद्भावना के लिये प्रतिकूल होगा।

- इसने यह भी सुझाव दिया कि **व्यक्तिगत कानूनों में सुधार संशोधनों द्वारा किया जाना चाहिये, न कि प्रतिस्थापन द्वारा।**
- हाल ही में **भारत के 22वें वधि आयोग** ने UCC के संबंध में सामान्य जनता के साथ-साथ मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों की राय और सुझाव लेने का निर्णय किया है।

UCC को लागू करने में चुनौतियाँ:

- **राजनीतिक जड़ता:** किसी भी राजनीतिक दल ने इस **संहिता को अधिनियमित करने की ईमानदारी पूर्वक और नियमित तौर पर प्रतिबद्धता** नहीं दिखाई है क्योंकि इसे हमेशा से ही



स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/need-for-ucc-in-india>

